

# शिक्षा और नवाचार: गोवा बोर्ड का भविष्य की ओर कदम

प्रियंका जी जोशीलकर<sup>1\*</sup>

1. रिसर्च स्कॉलर, सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय, महाराष्ट्र, भारत  
joshilkarpriyanka79@gmail.com

सारांश: इक्कीसवीं सदी में शिक्षा का स्वरूप पूर्णतः परिवर्तित हो चुका है। अब शिक्षा केवल पाठ्यपुस्तकों, कक्षा शिक्षण और परीक्षा आधारित प्रणाली तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह नवाचार, डिजिटल साक्षरता, कौशल विकास, और जीवनोपयोगी अनुभवों पर आधारित हो गई है। इसी परिवर्तनशील संदर्भ में गोवा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल (GBSHSE) द्वारा की गई विविध शैक्षिक पहलों ने एक नवीन दिशा प्रदान की है। इस शोध-पत्र में गोवा शिक्षा मंडल की नवीन शैक्षिक नीतियों, नवाचारी कार्यक्रमों, मूल्यांकन प्रणाली में किए गए सुधारों, डिजिटल शिक्षा की ओर उठाए गए ठोस कदमों, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप उनके समायोजन का समग्र विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। यह शोध इस बात का विश्लेषण करता है कि गोवा बोर्ड द्वारा अपनाई गई नीतियाँ किस प्रकार न केवल शिक्षा प्रणाली को समावेशी, सृजनात्मक एवं व्यवहारिक बना रही हैं, बल्कि छात्र-केन्द्रित, कौशल-मुख्य और भविष्योन्मुख शिक्षा की ओर अग्रसर भी कर रही हैं। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी, बहु-आयामी अधिगम, शिक्षक-प्रशिक्षण, आंतरिक मूल्यांकन की भूमिका, और डिजिटल अधिगम संसाधनों के प्रभाव का भी गहन परीक्षण किया गया है। इस शोध का उद्देश्य यह भी है कि स्थानीय आवश्यकता एवं वैश्विक दृष्टिकोण के मध्य संतुलन बनाते हुए किस प्रकार गोवा बोर्ड शिक्षा को अधिक प्रासंगिक, नवाचारशील और परिवर्तनशील बना रहा है। शोध में विभिन्न शैक्षिक आँकड़ों, नीतिगत दस्तावेज़ों, तथा क्षेत्रीय विद्यालयों के अनुभवों के आधार पर प्रस्तुत निष्कर्ष शिक्षा के भविष्य की स्पष्ट झलक प्रस्तुत करते हैं।

**मुख्य शब्द:** शिक्षा प्रणाली, नवाचार, डिजिटल साक्षरता, कौशल विकास, मूल्यांकन प्रणाली, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, समावेशिता, शैक्षिक सुधार, व्यवहारिक अधिगम, छात्र-केन्द्रित शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण, गोवा शिक्षा मंडल

----- X -----

## प्रस्तावना

गोवा, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक छोटा किन्तु अत्यंत प्रगतिशील राज्य है, जिसने न केवल आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी नवाचार एवं गुणवत्ता के माध्यम से एक प्रेरणादायक दृष्टांत प्रस्तुत किया है। ऐतिहासिक रूप से गोवा की शिक्षा प्रणाली पर पुर्तगाली शासन का प्रभाव रहा है, जिससे इसकी शैक्षिक सोच में प्रारम्भ से ही आधुनिकता एवं वैश्विक दृष्टिकोण का समावेश देखा गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् गोवा ने भारत के शिक्षा ढाँचे को अंगीकृत करते हुए भी अपनी क्षेत्रीय आवश्यकताओं एवं वैश्विक प्रवृत्तियों के अनुरूप शिक्षा को नया स्वरूप देने का प्रयास किया है। आज के दौर में जब शिक्षा केवल पुस्तकों और कक्षा शिक्षण तक सीमित नहीं रही, गोवा ने डिजिटल माध्यमों, कौशल विकास, नैतिक मूल्यों एवं नवाचार आधारित अधिगम पद्धतियों को अपनाकर अपनी शिक्षा व्यवस्था को समकालीन समय की माँगों के अनुरूप परिवर्तित किया है। गोवा की शिक्षा नीति का यह नवाचारपरक दृष्टिकोण विशेष रूप से गोवा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल की सक्रियता एवं दूरदर्शिता का परिणाम है, जिसने समय के अनुरूप नीतियों को क्रियान्वित करते हुए विद्यार्थियों को भविष्य की चुनौतियों हेतु तैयार करने में अग्रणी भूमिका निभाई है।

राज्य शिक्षा मंडल द्वारा प्रारम्भ की गई अनेक योजनाएँ जैसे – एक विद्यार्थी एक यंत्र योजना, विज्ञान-प्रौद्योगिकी-इंजीनियरी-कला एवं गणित पर आधारित समग्र अधिगम प्रणाली, स्थानीय संस्कृति पर आधारित पाठ्यक्रम निर्माण, और मूल्यपरक शिक्षा के समावेशन जैसे प्रयास उल्लेखनीय हैं। विशेषकर डिजिटल शिक्षा को गाँवों तक पहुँचाने के लिए विद्यालयों में तकनीकी उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। शिक्षकों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ताकि वे नवीनतम शिक्षण विधियों, तकनीकी प्रयोगों एवं छात्र-केन्द्रित पद्धतियों को आत्मसात कर सकें। कोविड-19 के संकट काल में भी गोवा ने डिजिटल मंचों जैसे – ई-पाठशाला, दीक्षा मंच, और गूगल कक्षा इत्यादि का उपयोग करते हुए शिक्षण कार्य को निरंतर बनाये रखा। इस अवधि में राज्य सरकार ने अध्ययन सामग्री को ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों रूपों में छात्रों तक पहुँचाने हेतु विशेष अभियान चलाया। यह पहल विशेष रूप से ग्रामीण एवं वंचित समुदायों के लिए उपयोगी सिद्ध हुई।

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने स्मार्ट विद्यालय योजना, नवाचार प्रयोगशाला, पुस्तकालय समृद्धि अभियान, और छात्र कल्याण योजनाओं जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यालयों के भौतिक एवं शैक्षणिक वातावरण को उन्नत बनाने का प्रयास किया है। इन पहलों ने न केवल छात्रों के सीखने के अनुभव को समृद्ध किया, बल्कि उनमें नेतृत्व, आत्मविश्वास एवं व्यावसायिक कौशल के बीज भी बोये हैं।

इस प्रस्तावना खंड के माध्यम से हम गोवा की शिक्षा नीति की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वर्तमान अवस्थिति, नीति निर्माण की दिशा, एवं शैक्षिक नवाचारों की समग्र रूपरेखा को समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही, यह अध्याय आगामी खंडों के लिए एक बौद्धिक आधार निर्मित करेगा, जिनमें

हम गोवा राज्य की शिक्षा प्रणाली की संरचना, कार्यप्रणाली, चुनौतियाँ एवं सम्भावनाओं का गहन विश्लेषण करेंगे। इस प्रकार गोवा की शिक्षा नीति का यह अध्ययन केवल क्षेत्रीय संदर्भ में नहीं, अपितु राष्ट्रीय शैक्षिक विमर्श में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

### गोवा राज्य की सामाजिक-शैक्षिक पृष्ठभूमि

गोवा राज्य की सामाजिक-शैक्षिक पृष्ठभूमि विविधताओं से परिपूर्ण है, जो इसके ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक परिवर्तनों से गहराई से जुड़ी हुई है। कभी पुर्तगाली उपनिवेश के रूप में स्थापित यह क्षेत्र, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत गणराज्य का अभिन्न अंग बना और तभी से यहाँ की शिक्षा नीति ने एक नये स्वरूप को ग्रहण किया। प्रारंभ से ही गोवा ने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन एवं समावेशिता का माध्यम माना, जिसके फलस्वरूप यहाँ की साक्षरता दर अन्य राज्यों की तुलना में उल्लेखनीय रूप से अधिक रही है। गोवा में शिक्षा केवल औपचारिक प्रमाणपत्र प्राप्त करने का साधन न रहकर, सामाजिक न्याय, समता और आर्थिक प्रगति का आधार बन चुकी है। राज्य सरकार द्वारा वंचित, आदिवासी, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए विशेष योजनाएँ लागू की गई हैं, जिनमें छात्रवृत्ति, पोषाहार, निःशुल्क पुस्तकें, ड्रेस और तकनीकी सहायता शामिल हैं, ताकि वे भी शिक्षा की मुख्यधारा में समान रूप से सम्मिलित हो सकें।

ग्रामीण क्षेत्रों तक विद्यालयों की पहुँच सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने आधारभूत ढाँचे का विकास किया, जिसमें प्राथमिक विद्यालयों से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों तक सुविधाओं का विस्तार किया गया। यहाँ के समाज में शिक्षित वर्ग की निरंतर बढ़ती भागीदारी न केवल शिक्षा के महत्व को दर्शाती है, बल्कि यह भी प्रमाणित करती है कि शासन और समाज ने मिलकर शिक्षा को एक सशक्त परिवर्तनकारी उपकरण के रूप में अपनाया है। गोवा जैसे छोटे राज्य में, जहाँ जनसंख्या सीमित है, वहाँ संसाधनों का कुशल प्रबंधन करते हुए राज्य ने डिजिटल शिक्षा, पुस्तकालय सुविधा, बालिका शिक्षा को प्राथमिकता देने और बाल श्रम जैसी सामाजिक समस्याओं के समाधान हेतु शिक्षा को एक व्यापक सामाजिक यंत्र के रूप में विकसित किया है। शिक्षा के प्रति लोगों की जागरूकता, प्रशासन की तत्परता, तथा शिक्षकों का समर्पण – इन सभी कारकों ने मिलकर गोवा को एक समावेशी, न्यायपूर्ण और आधुनिक शिक्षा प्रणाली की दिशा में प्रेरित किया है, जो देश के अन्य राज्यों के लिए भी अनुकरणीय बन चुकी है।

### गोवा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की भूमिका

गोवा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (गोवा बोर्ड) की स्थापना राज्य में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा को व्यवस्थित, समुचित एवं समावेशी बनाने के उद्देश्य से की गई थी। यह मंडल केवल परीक्षा आयोजित करने अथवा प्रमाणपत्र प्रदान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राज्य की संपूर्ण स्कूली शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता, संरचना और कार्यप्रणाली के नियमन तथा विकास का केंद्र बिंदु है। बोर्ड का प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समसामयिक, व्यावहारिक, नवाचारी और नैतिक शिक्षा प्रदान करना है ताकि वे न केवल अकादमिक रूप से सफल हो सकें, बल्कि जीवन कौशल, सामाजिक उत्तरदायित्व और वैश्विक दृष्टिकोण में भी दक्ष बन सकें।

गोवा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा पाठ्यक्रमों को समयानुकूल बनाने हेतु नियमित रूप से समीक्षाएं की जाती हैं, जिनमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के अनुरूप परिवर्तन शामिल हैं। इसके अंतर्गत विद्यालयों में बहु-विषयकता, मूल्यपरक शिक्षा, कौशल आधारित अधिगम, और क्षेत्रीय आवश्यकता के अनुसार विषयों के चयन की सुविधा को बढ़ावा दिया गया है। बोर्ड ने शिक्षकों के सतत व्यावसायिक विकास को आवश्यक मानते हुए प्रशिक्षण कार्यशालाओं, वेबिनार, और नवाचार प्रयोगशालाओं का आयोजन सुनिश्चित किया है, जिससे शिक्षक आधुनिक शिक्षण तकनीकों, डिजिटल माध्यमों, और छात्र-केंद्रित पद्धतियों में पारंगत हो सकें। परीक्षा प्रणाली में सुधार के अंतर्गत बोर्ड ने अंक आधारित प्रणाली के स्थान पर आकलन आधारित, बहुस्तरीय मूल्यांकन प्रणाली को अपनाया है, जिसमें आंतरिक मूल्यांकन, परियोजना कार्य, मौखिक परीक्षा, एवं व्यावहारिक प्रदर्शन को भी महत्त्व दिया गया है। इससे विद्यार्थी केवल रटने तक सीमित नहीं रहते, बल्कि उनकी संज्ञानात्मक, विश्लेषणात्मक, रचनात्मक एवं भावनात्मक क्षमताओं का समुचित विकास होता है।

डिजिटल माध्यमों का समावेश भी बोर्ड की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसके अंतर्गत ऑनलाइन पठन सामग्री, वीडियो शिक्षण, डिजिटल लाइब्रेरी, एवं एकीकृत छात्र पोर्टल जैसी सुविधाओं को शुरू किया गया है। कोविड-19 के दौर में भी GBSHSE ने शैक्षिक गतिविधियों को बाधित नहीं होने दिया, बल्कि डिजिटलीकरण को गति देते हुए शिक्षण कार्य को नए स्वरूप में प्रस्तुत किया। बोर्ड द्वारा "एक विद्यार्थी – एक यंत्र" योजना, विद्यालय स्तर पर ई-संसाधनों की उपलब्धता, और स्मार्ट कक्षा जैसी योजनाओं को कार्यान्वित किया गया है। गोवा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शिक्षा को स्थानीय संस्कृति, वैश्विक मांगों और राष्ट्रीय लक्ष्यों के समन्वय से जोड़ते हुए विद्यार्थियों में समग्र व्यक्तित्व विकास की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उसकी योजनाएँ केवल अकादमिक सफलता नहीं बल्कि नैतिक बोध, सामाजिक उत्तरदायित्व, पर्यावरणीय चेतना और तकनीकी दक्षता को भी विकसित करने में सहायक रही हैं। इस प्रकार गोवा बोर्ड राज्य की शिक्षा प्रणाली का एक मजबूत स्तंभ बनकर उभर रहा है, जिसकी कार्यप्रणाली और दृष्टिकोण अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है।

### 21वीं सदी की शिक्षा की अवधारणा

इक्कीसवीं सदी में शिक्षा की परिभाषा व्यापक रूप से परिवर्तित हो चुकी है। अब यह केवल पाठ्यपुस्तकों तक सीमित ज्ञान प्रदान करने का माध्यम

नहीं रह गया है, बल्कि यह एक समग्र विकास की प्रक्रिया बन गई है, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल परीक्षा के लिए तैयार करना नहीं, बल्कि उन्हें जीवन के विभिन्न पहलुओं में सक्षम बनाना है। आज की शिक्षा को बहुआयामी दृष्टिकोण से देखा जाता है, जिसमें नवाचार, तकनीकी दक्षता, रचनात्मकता, आलोचनात्मक चिंतन, समस्या समाधान की क्षमता, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, सामाजिक एवं नैतिक उत्तरदायित्व जैसे तत्वों का समावेश आवश्यक हो गया है।

गोवा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल (GBSHSE) ने इस आधुनिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए विद्यार्थियों को वैश्विक स्तर की प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने के लिए कई कदम उठाए हैं। बोर्ड द्वारा डिजिटल शिक्षण सामग्री का विकास, ऑनलाइन कक्षाओं की व्यवस्था, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) का शिक्षण में समावेश, तथा बहुभाषिक अधिगम का प्रोत्साहन – ये सभी प्रयास इस बात का प्रमाण हैं कि गोवा राज्य की शिक्षा नीति भविष्य के लिए तैयार शिक्षार्थियों को गढ़ने हेतु प्रतिबद्ध है।

### शिक्षा में नवाचार और डिजिटल साक्षरता की आवश्यकता

आज का समय 'सूचना युग' के रूप में जाना जाता है, जहाँ ज्ञान एवं सूचना का प्रवाह अत्यंत तीव्र गति से हो रहा है। तकनीक का प्रभाव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में गहराई से महसूस किया जा सकता है, और शिक्षा इस परिवर्तन से अछूती नहीं रह सकती। ऐसे परिदृश्य में डिजिटल साक्षरता केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि एक अनिवार्य शैक्षिक आवश्यकता बन चुकी है। एक ऐसा विद्यार्थी जो तकनीकी रूप से दक्ष नहीं है, वह आज की प्रतिस्पर्धात्मक दुनिया में पिछड़ सकता है।

इन्हीं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए गोवा बोर्ड ने नवाचार आधारित शिक्षा को अपनी कार्यनीति का केंद्रीय तत्व बनाया है। विद्यालयों में स्मार्ट कक्षा परियोजनाओं का विस्तार किया गया है, जिससे छात्रों को ऑडियो-विजुअल माध्यमों से शिक्षण सामग्री प्राप्त होती है। डिजिटल पुस्तकालयों की स्थापना, मोबाइल एप्लिकेशन आधारित शिक्षण, ऑनलाइन मूल्यांकन प्रणाली, और ई-पाठ्यक्रमों की शुरुआत – ये सभी पहल गोवा की डिजिटल शिक्षा को एक नई दिशा प्रदान कर रही हैं। इसके अतिरिक्त, शिक्षकों को तकनीकी प्रशिक्षण देने हेतु विभिन्न कार्यशालाएँ, वेबिनार और शैक्षिक सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं ताकि वे नवीनतम तकनीकों का प्रभावी ढंग से प्रयोग कर सकें।

### राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और गोवा बोर्ड की तत्परता

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा प्रणाली में एक ऐतिहासिक एवं दूरगामी परिवर्तन लाने वाला दस्तावेज है। यह नीति शिक्षा को समग्र, लचीला, बहुभाषिक, और व्यवहारिक जीवन कौशल आधारित बनाने पर केंद्रित है। इसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया है कि शिक्षा प्रत्येक विद्यार्थी की प्रतिभा, रुचि एवं सामाजिक पृष्ठभूमि के अनुरूप हो। गोवा बोर्ड ने इस नीति के क्रियान्वयन हेतु तत्परता दर्शाते हुए कई कदम उठाए हैं। इनमें पाँच + तीन + तीन + चार (5+3+3+4) शिक्षा संरचना को अपनाना, क्षेत्रीय भाषा में प्रारंभिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना, व्यावसायिक शिक्षा को माध्यमिक स्तर से ही पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाना, तथा समावेशी एवं सतत अधिगम की अवधारणा को मजबूत करना प्रमुख हैं। गोवा सरकार और बोर्ड द्वारा नीति के प्रत्येक पहलू को समझने, लागू करने और शिक्षकों को उससे अवगत कराने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों, परामर्श कार्यशालाओं एवं शैक्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस नीति के माध्यम से शिक्षा को स्थानीय और वैश्विक संदर्भ में उपयोगी बनाने की दिशा में गोवा राज्य ने अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाया है।

### शोध की आवश्यकता और प्रासंगिकता

21वीं सदी की शिक्षा, जो निरंतर परिवर्तित होती सामाजिक, आर्थिक एवं तकनीकी पृष्ठभूमि में कार्यरत है, वह केवल औपचारिक प्रमाणपत्र प्राप्त करने का माध्यम नहीं रही, बल्कि यह जीवन निर्माण का प्रमुख आधार बन चुकी है। ऐसे समय में जब शिक्षा नीतियाँ और शैक्षणिक प्रक्रियाएँ तीव्रता से परिवर्तित हो रही हों, तब उन पर सम्यक अनुसंधान करना, उनकी उपयोगिता और प्रभाव का मूल्यांकन करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। गोवा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा अपनाई गई आधुनिक नीतियाँ, नवाचारी प्रयास, और डिजिटल समावेशन – इन सभी का प्रभाव कितना प्रभावशाली है, यह जानने के लिए गंभीर एवं व्यवस्थित अध्ययन की आवश्यकता है। यह शोध न केवल गोवा राज्य की शैक्षिक प्रगति को समझने में सहायक होगा, बल्कि यह भारत के अन्य राज्यों तथा नीति निर्माताओं के लिए एक मॉडल और दिशा निर्देश के रूप में कार्य करेगा। यह अध्ययन शिक्षा में क्षेत्रीय नवाचारों की भूमिका, डिजिटल साक्षरता की प्रभावशीलता, तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के धरातलीय क्रियान्वयन की वास्तविकताओं को उजागर करेगा, जिससे एक निष्पक्ष एवं तथ्यात्मक मूल्यांकन प्रस्तुत किया जा सके। इस प्रकार यह शोध न केवल शैक्षिक दृष्टि से प्रासंगिक है, बल्कि नीति, प्रशासन एवं समाजशास्त्र की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

### अनुसंधान की पद्धति

शोध किसी भी अकादमिक अध्ययन की आत्मा होता है, जो उसे केवल वैचारिक विमर्श से आगे ले जाकर एक वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ और प्रमाणिक संरचना प्रदान करता है। वर्तमान शोध-पत्र में अनुसंधान की पद्धति को इस प्रकार संरचित किया गया है कि गोवा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल (GBSHSE) द्वारा किए गए शैक्षिक नवाचारों, डिजिटल एकीकरण, और राष्ट्रीय

शिक्षा नीति 2020 के प्रति उसकी सक्रियता का गहराई से परीक्षण किया जा सके। चूँकि यह अध्ययन एक वृहत सामाजिक-शैक्षिक परिप्रेक्ष्य से जुड़ा हुआ है, अतः इसकी वैज्ञानिकता बनाए रखने हेतु अनुसंधान की प्रत्येक अवस्था को विधिवत परिभाषित, वर्गीकृत और सुस्पष्ट किया गया है। इस अध्ययन का आधार पूर्णतः द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त सामग्री पर आधारित है, जिससे नीति, क्रियान्वयन, कार्यक्रम और संस्थागत प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण किया जा सके। इस विधि से गोवा की शैक्षिक स्थिति का न केवल वर्णनात्मक अध्ययन किया गया है, बल्कि विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से उसकी प्रभावशीलता, समावेशिता और नवाचार की दिशा में उसकी गति का मूल्यांकन भी किया गया है। यह अनुसंधान पद्धति शोध-पत्र को एक वैज्ञानिक, संरचित एवं प्रमाणिक आधार प्रदान करती है। दस्तावेज़ विश्लेषण विधि के माध्यम से गोवा की शिक्षा प्रणाली में हुए नवाचारों, डिजिटल साक्षरता के प्रयासों तथा नीति क्रियान्वयन की प्रक्रिया को समझना संभव हुआ। विषय के गुणात्मक स्वरूप को ध्यान में रखते हुए यह अनुसंधान शिक्षा नीति, प्रशासनिक कार्यप्रणाली, और संस्थागत विकास का गहन मूल्यांकन प्रस्तुत करता है, जो न केवल शैक्षिक शोध के लिए उपयोगी है, बल्कि नीति-निर्माताओं एवं कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए भी मार्गदर्शक सिद्ध हो सकता है।

### अनुसंधान की प्रकृति

यह शोध गुणात्मक (गुणवत्तात्मक) प्रकृति का है, जिसमें मात्रात्मक आँकड़ों के स्थान पर विचारों, नीतियों, प्रक्रियाओं और प्रलेखित साक्ष्यों का गहन अध्ययन किया गया है। गुणात्मक अध्ययन में शोधकर्ता घटनाओं, परिवर्तनों और रणनीतियों के पीछे के निहितार्थों को समझने का प्रयास करता है। इस अध्ययन में विशेष रूप से गोवा बोर्ड की शिक्षा नीति, नवाचार की दिशा में किए गए प्रयास, डिजिटल साधनों का समावेश, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन की व्याख्या की गई है। इसमें वर्णनात्मक दृष्टिकोण (जहाँ तथ्यों का यथावत प्रस्तुतीकरण होता है) तथा विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण (जहाँ तथ्यों के आधार पर गहराई से विवेचन होता है) दोनों को सम्मिलित किया गया है।

### अनुसंधान विधि का प्रकार

वर्तमान अध्ययन में दस्तावेज़ विश्लेषण विधि को अनुसंधान की प्रमुख तकनीक के रूप में चुना गया है। यह विधि गुणात्मक अनुसंधान की एक प्रभावशाली शाखा है, जो किसी विषय पर उपलब्ध पूर्व प्रकाशित स्रोतों, सरकारी प्रतिवेदनों, नीति पत्रों, और शैक्षिक रिपोर्टों का आलोचनात्मक परीक्षण कर उनके निष्कर्ष निकालने में सहायक होती है। इस अध्ययन में गोवा बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट, नीति दस्तावेज़, शिक्षा विभाग की वेबसाइट, समाचार पत्रों तथा शैक्षणिक मंचों से प्राप्त सामग्रियों का उपयोग किया गया है। यह विधि इसलिये उपयुक्त है क्योंकि यह बिना प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के मौजूदा दस्तावेज़ों के माध्यम से शिक्षा के बदलते स्वरूप को समग्रता से उजागर कर सकती है।

### जानकारी संग्रह की प्रक्रिया

शोध-पत्र में प्रयुक्त जानकारी का संग्रह सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध रूप से निम्नलिखित द्वितीयक स्रोतों से किया गया है:

गोवा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल की वार्षिक प्रतिवेदन: इन प्रतिवेदनों से पाठ्यचर्या में किए गए परिवर्तनों, मूल्यांकन प्रणाली में सुधार, शिक्षक प्रशिक्षण योजनाओं तथा डिजिटल अधिगम से संबंधित अद्यतन जानकारी प्राप्त की गई।

गोवा राज्य शिक्षा विभाग की आधिकारिक जालस्थल: राज्य की शिक्षा से संबंधित योजनाएँ, बजट विवरण, नीति दस्तावेज़ एवं कार्यक्रमों की क्रियान्वयन रिपोर्टें यहाँ से प्राप्त की गईं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: भारत सरकार द्वारा घोषित यह नीति वर्तमान अध्ययन का केन्द्रीय दस्तावेज़ है, जिसके माध्यम से गोवा राज्य की रणनीतियों और नीतिगत तत्परता का मूल्यांकन किया गया।

एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (यू-डाइस+): यह देशव्यापी आँकड़ा प्रणाली शैक्षिक स्थिति का तथ्यों पर आधारित चित्र प्रस्तुत करती है। गोवा में विद्यालयों की स्थिति, नामांकन अनुपात, डिजिटल सुविधा, शिक्षक-छात्र अनुपात आदि से संबंधित आँकड़े यहाँ से संकलित किए गए।

समाचार पत्र एवं शैक्षणिक समाचार मंच: देश के प्रमुख दैनिक पत्रों जैसे – 'द हिंदू', 'इंडियन एक्सप्रेस', 'टाइम्स ऑफ इंडिया' तथा शिक्षा केंद्रित मंचों जैसे – 'इंडिया एजुकेशन डायरी', 'एडेक्स लाइव' आदि से नवाचारों की जानकारी तथा विशेषज्ञों की राय का संकलन किया गया।

### तुलनात्मक अध्ययन – अन्य राज्यों से तुलना का औचित्य

इस शोध में गोवा की शिक्षा प्रणाली का विश्लेषण करते समय अन्य प्रगतिशील राज्यों – जैसे केरल, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक – की शिक्षा नीतियों, नवाचारों, तथा डिजिटल पहलों से तुलनात्मक समीक्षा की गई है। इस तुलना का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि गोवा शिक्षा क्षेत्र में कहाँ तक अग्रसर है, और किन क्षेत्रों में वह अन्य राज्यों की तुलना में एक आदर्श मॉडल प्रस्तुत करता है। यह तुलनात्मक दृष्टिकोण शोध को केवल विवरणात्मक न रखकर विश्लेषणात्मक आयाम प्रदान करता है।

### विश्लेषण की प्रक्रिया

संग्रहीत समस्त जानकारी को प्राथमिक वर्गों में विभाजित किया गया – जैसे पाठ्यचर्या सुधार, शिक्षक प्रशिक्षण, डिजिटल अधिगम, नीति क्रियान्वयन, एवं छात्र-हित कार्यक्रम। प्रत्येक वर्ग के अंतर्गत नीतियों एवं कार्यान्वयन के प्रभाव, चुनौतियाँ, एवं सुधारात्मक सुझावों की समीक्षा की गई। इसमें विवेचनात्मक उपकरणों का प्रयोग कर गहराई से विश्लेषण किया गया, जिससे तथ्य, प्रभाव और सिफारिशें स्पष्ट रूप से प्रतिपादित हो सकीं।

### सीमाएँ

- यह शोध पूर्णतः द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है, अतः इसमें प्रत्यक्ष सर्वेक्षण, संवाद अथवा साक्षात्कार विधियों का समावेश नहीं किया गया है।
- अध्ययन की समय सीमा केवल वर्ष 2019 से 2024 तक सीमित रखी गई है, जिससे पहले या बाद की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएँ शोध के दायरे से बाहर रह गई हैं।
- कुछ दस्तावेजों की अद्यतन स्थिति उपलब्ध न होने के कारण सीमित आँकड़ों से निष्कर्ष निकाले गए हैं, जो व्यापक सत्यापन के लिए आगे के शोध की आवश्यकता की ओर संकेत करते हैं।

### गोवा बोर्ड की संरचना एवं कार्यप्रणाली

गोवा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल (GBSHSE) राज्य की शिक्षा प्रणाली का केंद्रीय स्तंभ है, जिसकी संरचना, कार्य एवं दायित्व न केवल प्रशासनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि शैक्षिक गुणवत्ता, नवाचार और समावेशिता के विस्तार में भी इसकी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। इस अध्याय में हम बोर्ड की संरचना, स्थापना के उद्देश्य, प्रशासनिक ढाँचे, और कार्यों का विस्तृत विश्लेषण करेंगे, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि किस प्रकार ने राज्य की शिक्षा को दिशा, दृष्टि और गति प्रदान की है। गोवा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शिक्षा को केवल परीक्षा और प्रमाणपत्र तक सीमित न रखकर उसे समावेशी, तकनीक-प्रेरित, और नवाचारयुक्त स्वरूप प्रदान किया है। इसकी कार्यप्रणाली राज्य की शिक्षा नीति को जमीनी स्तर तक लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह बोर्ड न केवल प्रशासनिक दृष्टि से सशक्त है, बल्कि शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन के माध्यम के रूप में स्थापित करने हेतु भी कृतसंकल्पित है।

### बोर्ड का गठन एवं कार्य

गोवा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल की स्थापना सन् 1975 में की गई थी, जब गोवा एक केंद्रशासित प्रदेश के रूप में कार्य कर रहा था। शिक्षा के बढ़ते प्रसार, मानकीकरण, और गुणवत्तापूर्ण प्रशासन के उद्देश्य से इस मंडल की स्थापना की गई। इसका प्रमुख कार्य राज्य के सभी माध्यमिक (कक्षा 10) और उच्चतर माध्यमिक (कक्षा 12) स्तर के विद्यालयों की मान्यता, निरीक्षण, संचालन और नियमन करना है। बोर्ड का कार्य केवल परीक्षा आयोजित करना भर नहीं है, बल्कि यह एक समग्र शैक्षिक तंत्र का निर्माण करता है, जिसमें विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास, शिक्षकों की दक्षता, विद्यालयों की गुणवत्ता और पाठ्यचर्या की प्रासंगिकता को सुनिश्चित करना भी सम्मिलित है। यह बोर्ड शिक्षा नीति निर्धारण, पाठ्यक्रम विकास, मूल्यांकन प्रणाली के

आधुनिकीकरण, और नीति क्रियान्वयन में राज्य सरकार का प्रमुख भागीदार है। बोर्ड की संरचना में अध्यक्ष, सचिव, विषय विशेषज्ञ, प्रशासनिक अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक, और तकनीकी परामर्शदाता जैसे पद सम्मिलित होते हैं। इनके माध्यम से नीति निर्माण से लेकर कार्यान्वयन तक की प्रक्रिया प्रभावी रूप से संचालित की जाती है। साथ ही, इसमें सलाहकार समितियाँ भी गठित की जाती हैं, जो समय-समय पर पाठ्यक्रम संशोधन, मूल्यांकन सुधार, एवं शिक्षक प्रशिक्षण पर सुझाव देती हैं।

### बोर्ड के प्रमुख कार्य – विस्तारपूर्वक

गोवा बोर्ड के कार्य केवल सीमित दायरे में नहीं आते, बल्कि ये शिक्षा की गुणवत्ता, पहुँच, समानता और नवीनता सुनिश्चित करने की दिशा में विस्तृत रूप से कार्य करते हैं। प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं:

**(क) पाठ्यचर्या निर्माण एवं संशोधन:** बोर्ड समय-समय पर विभिन्न विषयों की पाठ्यचर्या की समीक्षा कर उसमें सुधार करता है ताकि वह छात्रों की रुचि, वर्तमान सामाजिक-वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप हो। इसमें स्थानीय भाषा, संस्कृति और व्यावसायिक दक्षताओं को भी महत्व दिया जाता है।

**(ख) परीक्षा प्रणाली का संचालन:** कक्षा 10 और 12 की सार्वजनिक परीक्षाओं का आयोजन, प्रश्न पत्र निर्माण, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन, परिणाम घोषित करना और प्रमाण-पत्र प्रदान करना – ये सभी कार्य बोर्ड की निगरानी में होते हैं। बोर्ड ने परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता और निष्पक्षता को सुनिश्चित किया है।

**(ग) शिक्षकों का प्रशिक्षण एवं सतत विकास:** बोर्ड शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के लिए नियमित रूप से प्रशिक्षण शिविर, कार्यशालाएँ और वेबिनार आयोजित करता है, जिससे वे नवीनतम शिक्षण विधियों, तकनीकी कौशल और मूल्यपरक शिक्षा के प्रति सजग रहें।

**(घ) समावेशी शिक्षा का प्रोत्साहन:** बोर्ड विशेष आवश्यकता वाले छात्रों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के लिए विशेष योजनाएँ चलाता है। छात्रवृत्तियाँ, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें, स्कूल ट्रांसपोर्ट सुविधा और बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन जैसे उपक्रम इसके उदाहरण हैं।

**(ङ) डिजिटल शिक्षण एवं नवाचार:** डिजिटल माध्यमों जैसे स्मार्ट क्लास, ई-बुक्स, ऑनलाइन मूल्यांकन, और मोबाइल एप्स के माध्यम से अधिगम को तकनीक-संपन्न बनाना बोर्ड की एक बड़ी उपलब्धि है। यह पहल कोविड-19 के बाद विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध हुई।

**(च) शैक्षिक संस्थानों की मान्यता एवं निगरानी:** राज्य के सभी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की मान्यता, उनके भौतिक संसाधनों की समीक्षा, शिक्षकों की योग्यता की पुष्टि, तथा शैक्षिक प्रगति की निगरानी करना बोर्ड की प्रमुख जिम्मेदारी है।

**(छ) मूल्यांकन सुधार और नवाचार:** बोर्ड निरंतर मूल्यांकन प्रणाली (सीसीई), परियोजना आधारित अधिगम, गतिविधि आधारित मूल्यांकन तथा जीवन कौशल परीक्षण जैसे नवाचारों को बढ़ावा देता है, जिससे शिक्षा अधिक व्यवहारिक, रचनात्मक और छात्र-केंद्रित बन सके।

### शिक्षा में नवाचार की दिशा में उठाए गए कदम

21वीं सदी की शिक्षा का मूल उद्देश्य केवल पाठ्यक्रम आधारित ज्ञान प्रदान करना नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों को बदलते वैश्विक परिवेश के अनुरूप तैयार करना है। गोवा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रणाली में विविध नवाचारों को सम्मिलित किया है। गोवा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा शिक्षा में डिजिटल परिवर्तन, मूल्यांकन प्रणाली के नवाचार तथा कौशल आधारित शिक्षा के माध्यम से एक समावेशी, व्यवहारिक और भविष्य उन्मुख शैक्षणिक ढाँचे का निर्माण किया गया है। ये नवाचार न केवल विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धी समाज के लिए तैयार करते हैं, बल्कि उन्हें एक जिम्मेदार, आत्मनिर्भर और सशक्त नागरिक के रूप में भी विकसित करते हैं। यदि यही दिशा और गति बनी रही, तो गोवा का मॉडल निःसंदेह राष्ट्रीय स्तर पर एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करेगा। इन प्रयासों का मुख्य उद्देश्य

शिक्षा को अधिक समावेशी, तकनीकी रूप से सशक्त, व्यवहारिक तथा कौशल उन्मुख बनाना है। निम्नलिखित उपखंडों में इन नवाचारों की विस्तृत व्याख्या की गई है:

### डिजिटल परिवर्तन

गोवा बोर्ड ने शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल क्रांति लाने हेतु बहुआयामी योजनाएँ लागू की हैं। राज्य के अधिकांश सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों में ई-कक्षाओं (स्मार्ट क्लासरूम) की स्थापना की गई है, जिनमें प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड, ऑडियो-विजुअल सामग्री और इंटरनेट आधारित शिक्षण संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है। इन माध्यमों से शिक्षण अधिक प्रभावी, आकर्षक और संवादात्मक बन पाया है। राज्य सरकार ने विद्यार्थियों को स्वयं और दीक्षा जैसे राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा मंचों से जोड़ने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। इससे छात्रों को पाठ्यक्रम से संबंधित गुणवत्तापूर्ण ई-सामग्री उपलब्ध होती है, जो उनकी स्व-अधिगम क्षमता को भी विकसित करती है। डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए बोर्ड ने डिजिटल लाइब्रेरी, ऑनलाइन क्विज़, वीडियो व्याख्यान, तथा आभासी प्रयोगशालाओं की सुविधा प्रदान की है। विशेष रूप से कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (कृबु), डेटा विज्ञान, कोडिंग, और साइबर सुरक्षा जैसे विषयों को वैकल्पिक पाठ्यक्रमों में शामिल किया गया है। इन आधुनिक विषयों के माध्यम से छात्र वैश्विक तकनीकी प्रगति से परिचित होते हैं और उनमें भविष्य के रोज़गार के अनुकूल कौशल विकसित होते हैं।

### मूल्यांकन प्रणाली में सुधार

गोवा बोर्ड ने मूल्यांकन पद्धति में पारंपरिक परीक्षा-केंद्रित दृष्टिकोण के स्थान पर समग्र मूल्यांकन प्रणाली को अपनाने की दिशा में कई परिवर्तन किए हैं। इसके अंतर्गत सातत्यपूर्ण एवं समग्र मूल्यांकन को लागू किया गया है, जिसमें विद्यार्थियों की संपूर्ण शैक्षणिक यात्रा का आकलन विभिन्न मापदंडों पर वर्ष भर किया जाता है। केवल लिखित परीक्षा तक सीमित न रहते हुए, छात्र की गतिविधियों, व्यवहार, प्रस्तुतीकरण, संप्रेषण कौशल, एवं सहभागिता का भी मूल्यांकन किया जाता है। परियोजना आधारित अधिगम को बढ़ावा देकर छात्र की रचनात्मकता, समस्या समाधान की क्षमता और व्यवहारिक समझ को महत्व दिया गया है। इससे छात्र केवल सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित नहीं रहते, बल्कि वे समाज और जीवन से जुड़ी समस्याओं का विश्लेषणात्मक हल निकालने में सक्षम बनते हैं। बोर्ड ने ओपन बुक परीक्षा की पायलट शुरुआत भी की है, जिसमें छात्रों को पुस्तक और संदर्भ सामग्री के साथ उत्तर देने की अनुमति होती है। यह नवाचार छात्रों की आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक सोच को परखने का प्रभावी माध्यम है। इसके अतिरिक्त पोर्टफोलियो मूल्यांकन प्रणाली भी अपनाई गई है, जिसमें छात्रों की व्यक्तिगत अभिरुचियों, शैक्षणिक प्रगति, कलात्मक प्रतिभा, एवं सामाजिक योगदान का दस्तावेजीकरण किया जाता है। यह विद्यार्थियों को एक समग्र शिक्षण अनुभव प्रदान करता है।

### कौशल आधारित शिक्षा

बदलते समय में रोजगार योग्य शिक्षा की माँग को ध्यान में रखते हुए गोवा बोर्ड ने कौशल आधारित शिक्षा को माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग बना दिया है। यह कदम न केवल अकादमिक प्रदर्शन के अतिरिक्त व्यावसायिक दक्षता को महत्व देता है, बल्कि यह छात्र को उद्योग-उन्मुख और रोजगार योग्य बनाता है। बोर्ड द्वारा कक्षा 9वीं से ही छात्रों को कृषि, पर्यटन एवं आतिथ्य सेवा, होटल प्रबंधन, स्वास्थ्य देखभाल, सौंदर्य एवं कल्याण, रिटेल प्रबंधन, ऑटोमोबाइल तकनीक, सूचना प्रौद्योगिकी आदि विषयों की शिक्षा प्रदान की जा रही है। इन विषयों को पढ़ाने के लिए बोर्ड ने विभिन्न औद्योगिक संस्थानों, कौशल प्रशिक्षण केंद्रों, और सरकारी विभागों के साथ समझौते भी किए हैं। बोर्ड परीक्षा के साथ-साथ इन विषयों में कौशल प्रमाणन (स्किल सर्टिफिकेशन) भी प्रदान किया जा रहा है, जो छात्रों के शैक्षणिक रिकार्ड में दर्ज किया जाता है। इससे छात्रों को उच्च शिक्षा में प्रवेश या व्यावसायिक दुनिया में अवसर प्राप्त करने में सहायता मिलती है। यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उस उद्देश्य को साकार करती है, जिसमें शिक्षा को रोजगार-उन्मुख और बहु-विकल्पीय मार्गदर्शित बनाने की बात की गई है।

### राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और गोवा बोर्ड

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था को एक समग्र, लचीला, समावेशी और कौशल-उन्मुख दिशा प्रदान करने का

प्रयास किया है। इस नीति के क्रियान्वयन में गोवा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने तत्परता दिखाई है और कई नवाचारों को सफलतापूर्वक अपने कार्यान्वयन में शामिल किया है। इस अध्याय में हम नीति के विभिन्न लक्ष्यों और गोवा बोर्ड की प्रतिक्रियाओं का विस्तृत विश्लेषण करेंगे।

### नीति के लक्ष्य और गोवा बोर्ड की प्रतिक्रिया

गोवा बोर्ड ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को न केवल सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया है, बल्कि इसके लक्ष्यों को व्यावहारिक धरातल पर उतारने हेतु ठोस कदम भी उठाए हैं। ECCE के अंतर्गत पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों को क्रियाशील बनाया गया है जहाँ बच्चों को खेल आधारित, गतिविधि आधारित और रचनात्मक अधिगम उपलब्ध कराया जाता है। मातृभाषा में शिक्षा के अंतर्गत कोंकणी एवं मराठी में पाठ्यपुस्तकों की व्यवस्था और शिक्षकों की नियुक्ति की गई है ताकि विद्यार्थियों को उनकी स्थानीय भाषा में प्रभावी रूप से शिक्षण मिल सके।

तालिका 1: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्य एवं गोवा बोर्ड द्वारा की गई पहलें

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्य	गोवा बोर्ड द्वारा की गई पहलें
5+3+3+4 शैक्षिक ढाँचे को अपनाना	ECCE (प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा) के अंतर्गत पूर्व-प्राथमिक शिक्षा का सुदृढीकरण
मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा	कक्षा 5 तक कोंकणी एवं मराठी में शिक्षण को प्रोत्साहन; स्थानीय भाषा में शिक्षकों की नियुक्ति
मूल्यांकन प्रणाली में सुधार	योग्यता आधारित प्रश्न-पत्रों का निर्माण; सतत और समग्र मूल्यांकन प्रणाली (CCE) का विस्तार
व्यावसायिक शिक्षा का प्रारंभिक चरण में समावेश	कक्षा 6 से ही कृषि, पर्यटन, ऑटोमोबाइल जैसे कौशल आधारित विषयों की शुरुआत और प्रमाणन प्रणाली
बहुभाषिक शिक्षा का संवर्धन	अंग्रेज़ी, कोंकणी, मराठी के साथ-साथ अन्य भारतीय भाषाओं में वैकल्पिक अधिगम की सुविधा
डिजिटल शिक्षा और तकनीकी समावेश	ई-कक्षा, मोबाइल एप आधारित शिक्षण, डिजिटल पुस्तकालय और SWAYAM/DIKSHA मंचों से जुड़ाव

मूल्यांकन प्रणाली में बदलाव करते हुए अब योग्यता आधारित प्रश्नों पर बल दिया जा रहा है, जो छात्रों के सोचने, विश्लेषण करने,

और समाधान प्रस्तुत करने की क्षमता को मापते हैं। इसके अलावा कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल कर विद्यार्थियों को प्रारंभ से ही कौशल आधारित प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे वे शिक्षा के साथ-साथ भविष्य के लिए व्यावसायिक रूप से तैयार हो सकें।

### शासन और शिक्षक प्रशिक्षण में नवाचार

गोवा बोर्ड ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के एक अन्य प्रमुख पहलू — शिक्षक प्रशिक्षण एवं शैक्षिक प्रशासन — में भी अत्यधिक सक्रिय भूमिका निभाई है। इसके अंतर्गत राज्य के दो प्रमुख संस्थान: DIET-Goa (District Institute of Education and Training) और SCERT-Goa (State Council of Educational Research and Training) के माध्यम से नियमित रूप से नवाचारपरक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं।

इन कार्यक्रमों की कुछ प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

- **डिजिटल सामग्री निर्माण:** शिक्षकों को पाठ्यसामग्री को डिजिटल स्वरूप में परिवर्तित करने, वीडियो लेक्चर बनाने, तथा ई-मॉड्यूल तैयार करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
- **सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) प्रशिक्षण:** स्मार्ट बोर्ड, प्रोजेक्टर, गूगल क्लासरूम, Zoom, तथा अन्य ई-लर्निंग टूल्स के उपयोग की तकनीकी जानकारी दी जा रही है।
- **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और डेटा विश्लेषण:** आगामी तकनीकी युग की आवश्यकताओं को देखते हुए शिक्षकों को AI के बुनियादी सिद्धांत, डेटा संग्रह एवं विश्लेषण से भी परिचित कराया जा रहा है।
- **शिक्षण रणनीतियों में नवाचार:** शिक्षकों को गतिविधि-आधारित शिक्षण, संवादपरक शिक्षण, बहु-बौद्धिक अधिगम (Multiple Intelligences) और मूल्य आधारित शिक्षा में दक्ष बनाया जा रहा है।
- **नीति जागरूकता कार्यक्रम:** NEP 2020 के प्रमुख प्रावधानों, जैसे कौशल शिक्षा, मातृभाषा में शिक्षा, तथा समावेशिता को शिक्षकों तक पहुँचाने हेतु विशेष जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं।

गोवा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने न केवल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्य को आत्मसात किया है, बल्कि उसे प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने हेतु संस्थागत, शैक्षिक और तकनीकी स्तर पर सशक्त कदम उठाए हैं। यह तत्परता और नवाचार गोवा को भारत के अन्य राज्यों के लिए एक प्रेरणास्पद उदाहरण बनाती है।

### छात्रों के लिए समावेशी और आधुनिक दृष्टिकोण

21वीं सदी की शिक्षा प्रणाली का मूल उद्देश्य केवल ज्ञान का संप्रेषण नहीं, बल्कि प्रत्येक विद्यार्थी की सामाजिक, मानसिक, शारीरिक और व्यावसायिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक समावेशी, संवेदनशील और आधुनिक शिक्षण वातावरण की स्थापना करना है। गोवा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल (GBSHSE) ने इस दिशा में कई ठोस प्रयास किए हैं जिनका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी छात्र—चाहे वह सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक या मानसिक रूप से किसी भी स्थिति में हो—शिक्षा की मुख्यधारा से वंचित न रहे।

### समावेशी शिक्षा के तत्व

गोवा बोर्ड द्वारा समावेशी शिक्षा के विचार को व्यवहार में लाने हेतु अनेक सशक्त कदम उठाए गए हैं, जो विविध सामाजिक समूहों को समान शैक्षणिक अवसर प्रदान करते हैं। विशेष रूप से दिव्यांग विद्यार्थियों, बालिकाओं, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों एवं आदिवासी समुदायों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए निम्नलिखित तत्व अपनाए गए हैं:

- **दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए सहायक तकनीकें:** दृष्टिबाधित छात्रों के लिए ब्रेल लिपि में पाठ्यसामग्री, स्पीच-टू-टेक्स्ट तकनीक, और स्क्रीन रीडर जैसे उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है। साथ ही बोर्ड परीक्षाओं में समयवृद्धि, सहलेखक की अनुमति, तथा प्रश्नपत्रों के विशेष प्रारूप प्रदान किए जाते हैं।
- **आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों के लिए छात्रवृत्तियाँ:** गोवा सरकार और बोर्ड मिलकर ऐसी योजनाएँ संचालित कर रहे हैं जिनके

अंतर्गत निर्धन परिवारों के बच्चों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें, गणवेश, परिवहन सुविधा और मासिक छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं।

- **बालिका शिक्षा को बढ़ावा:** 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान के तहत बोर्ड ने बालिकाओं के लिए अलग से परामर्श सत्र, सुरक्षा निगरानी प्रणाली, और सैनिटरी हाइजीन किट की व्यवस्था की है। उच्च शिक्षा हेतु प्रेरित करने के लिए विशेष छात्रवृत्तियाँ भी दी जा रही हैं।
- **आदिवासी और दूरदराज़ क्षेत्रों के लिए अध्ययन केंद्र:** राज्य के दुर्गम इलाकों, विशेषकर सह्याद्रि पर्वतीय क्षेत्रों में आदिवासी बच्चों के लिए विशेष अध्ययन केंद्र खोले गए हैं, जहाँ स्थानीय भाषाओं में शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। वहाँ के शिक्षक समुदाय की सामाजिक-सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से परिचित होते हैं जिससे शिक्षा अधिक प्रभावी होती है।
- **विद्यालय में समावेशी वातावरण का निर्माण:** बोर्ड ने समावेशी नीति के तहत विद्यालयों में ramps, टॉयलेट्स, तथा पहुँच योग्य कक्षाओं का निर्माण किया है, ताकि दिव्यांग विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से विद्यालय आ-जा सकें।

### करियर मार्गदर्शन एवं परामर्श

आज की शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने तक सीमित नहीं रह गई है; छात्रों को उनकी रुचियों, योग्यताओं और लक्ष्यों के अनुरूप भविष्य निर्माण की दिशा में मार्गदर्शन देना भी शिक्षा का अनिवार्य भाग बन गया है। इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए गोवा बोर्ड द्वारा निम्नलिखित प्रयास किए गए हैं:

- **करियर काउंसलिंग सेल की स्थापना:** अधिकांश माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में करियर काउंसलिंग सेल स्थापित किए गए हैं, जहाँ प्रशिक्षित करियर सलाहकारों के माध्यम से छात्रों को उनकी क्षमताओं, अभिरुचियों और सामर्थ्य के अनुसार उच्च शिक्षा और करियर विकल्पों की जानकारी दी जाती है।
- **राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी:** कक्षा 9वीं से ही छात्रों को NEET, JEE, CLAT, CUET जैसी परीक्षाओं के लिए बुनियादी मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके लिए विद्यालयों में स्पेशल कोचिंग क्लासेस, मॉडल टेस्ट, और मॉक इंटरव्यू की व्यवस्था की गई है।
- **मानसिक स्वास्थ्य परामर्श:** अध्ययन के दबाव, परीक्षा की चिंता, और व्यक्तिगत समस्याओं से निपटने के लिए स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदाता उपलब्ध कराए जा रहे हैं। योग कक्षाएं, मेडिटेशन सेशन और मनोवैज्ञानिक सहायता हेल्पलाइन जैसी सेवाएँ नियमित रूप से संचालित की जाती हैं।
- **व्यक्तित्व विकास एवं लाइफ स्किल्स:** छात्रों को संवाद कौशल, समय प्रबंधन, टीम वर्क, एवं आत्म-विश्वास जैसे जीवनोपयोगी गुणों को विकसित करने हेतु कार्यशालाएँ आयोजित की जाती हैं। इससे वे न केवल शिक्षित बल्कि आत्मनिर्भर और मानसिक रूप से सशक्त बनते हैं।

गोवा बोर्ड की यह समावेशी और आधुनिक दृष्टिकोण वाली रणनीति छात्रों को केवल शैक्षणिक दृष्टि से नहीं, बल्कि सामाजिक, मानसिक और व्यावसायिक रूप से भी सक्षम बनाती है। यह शिक्षा का वह स्वरूप है, जो प्रत्येक छात्र को उसकी विशेषताओं के साथ स्वीकार करता है, और उसे समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाने की दिशा में मार्ग प्रशस्त करता है। यदि यह मॉडल देश के अन्य राज्यों में भी अपनाया जाए, तो भारत की शिक्षा प्रणाली एक नई ऊँचाई को प्राप्त कर सकती है।

### चुनौतियाँ और समाधान

गोवा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल (GBSHSE) द्वारा शिक्षा में नवाचार, समावेशिता, और डिजिटल एकीकरण के क्षेत्र में कई सराहनीय पहल की गई हैं, परंतु इन प्रयासों के क्रियान्वयन में कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियाँ भी सामने आई हैं, जो नीति और व्यवहार के बीच की दूरी को दर्शाती हैं। इन चुनौतियों का समाधान यदि नियोजित, संरचित और सतत प्रक्रिया के रूप में किया जाए, तो न केवल इन बाधाओं को दूर किया जा सकता है, बल्कि शिक्षा प्रणाली को अधिक प्रभावी और न्यायसंगत बनाया जा सकता है।

सबसे पहली और प्रमुख चुनौती है डिजिटल विभाजन (डिजिटल डिवाइड), जहाँ ग्रामीण एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्र स्मार्ट डिवाइस, इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल शिक्षा संसाधनों तक नहीं पहुँच पाते। इस चुनौती का समाधान गोवा बोर्ड ने

सभी विद्यालयों में इंटरनेट सुविधा, कंप्यूटर लैब, और स्मार्ट क्लासरूम के विस्तार के माध्यम से किया है। “एक विद्यार्थी, एक यंत्र” योजना जैसी पहलों के माध्यम से विद्यार्थियों को व्यक्तिगत डिजिटल उपकरण भी प्रदान किए जा रहे हैं।

दूसरी चुनौती शिक्षकों के प्रशिक्षण की कमी है। कई बार शिक्षक नवीन तकनीकी उपकरणों, डिजिटल संसाधनों, और नई शिक्षा नीति के दृष्टिकोण से भलीभांति परिचित नहीं होते। इस समस्या का समाधान सतत व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों (CPD), प्रशिक्षक कार्यशालाओं और ICT आधारित प्रशिक्षण से किया जा रहा है। DIET-Goa और SCERT-Goa जैसे संस्थानों के सहयोग से शिक्षकों के लिए समय-समय पर ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन किया जा रहा है।

तीसरी चुनौती बहुभाषिक डिजिटल सामग्री की अनुपलब्धता है। चूंकि गोवा में कोंकणी, मराठी, अंग्रेज़ी आदि भाषाएँ प्रचलित हैं, ऐसे में एकरूप और सहज अधिगम के लिए विभिन्न भाषाओं में डिजिटल सामग्री की आवश्यकता रहती है। इस दिशा में गोवा बोर्ड ने स्थानीय भाषाओं में ई-पाठ्यपुस्तकें, ऑडियो-विजुअल मॉड्यूल, और इंटरैक्टिव शिक्षण सामग्री विकसित करने की दिशा में ठोस प्रयास शुरू किए हैं।

चौथी चुनौती मूल्यांकन प्रणाली में परिवर्तन की धीमी गति है। पारंपरिक मूल्यांकन से हटकर योग्यता आधारित, परियोजना केंद्रित और ओपन बुक परीक्षाओं को अपनाने में शिक्षकों, छात्रों और विद्यालय प्रशासन के स्तर पर मानसिक व तकनीकी तैयारी की आवश्यकता होती है। इसका समाधान बोर्ड ने पायलट परियोजनाओं के रूप में किया है, जिसमें चयनित विद्यालयों में नवीन मूल्यांकन पद्धति लागू कर उसका फीडबैक लिया जा रहा है। इस प्रकार सुधार प्रक्रिया को क्रमिक रूप से संस्थागत ढाँचे में समाहित किया जा रहा है।

ये चुनौतियाँ यद्यपि शिक्षा प्रणाली के समक्ष गम्भीर प्रश्न प्रस्तुत करती हैं, परंतु गोवा बोर्ड की नीतिगत स्पष्टता, तकनीकी हस्तक्षेप, और समावेशी दृष्टिकोण के माध्यम से इन समस्याओं से चरणबद्ध ढंग से निपटा जा रहा है। यदि यह प्रक्रिया निरंतर चलती रही, तो आने वाले समय में गोवा राज्य की शिक्षा प्रणाली इन चुनौतियों को अवसरों में बदलने में पूर्णतः सक्षम सिद्ध होगी।

### स्मार्ट कक्षाओं का विस्तार (2020–2025)

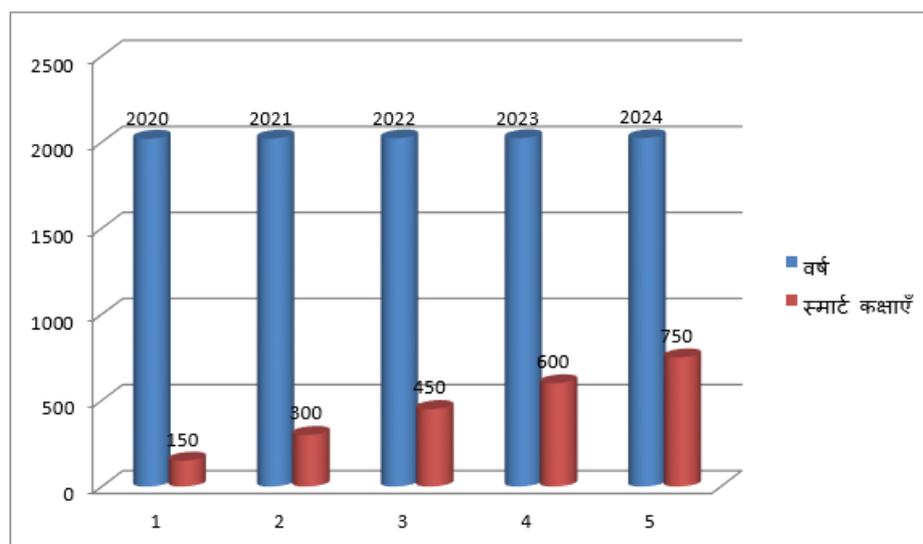
21वीं सदी की शिक्षा प्रणाली में तकनीकी समावेशन की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण हो गई है। विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के पश्चात, डिजिटल अधिगम और स्मार्ट कक्षाएँ विद्यालय शिक्षा का अनिवार्य हिस्सा बन गई हैं। इसी क्रम में गोवा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल (GBSHSE) ने शिक्षा को अधिक सुलभ, संवादात्मक और विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुकूल बनाने हेतु स्मार्ट कक्षाओं की स्थापना को प्राथमिकता दी है। यह प्रयास केवल एक तकनीकी बदलाव नहीं, बल्कि शिक्षण की पद्धति में गुणात्मक परिवर्तन का प्रतीक है।

वर्ष 2020 से 2025 के मध्य, गोवा बोर्ड ने एक क्रमिक और रणनीतिक योजना के तहत स्मार्ट कक्षा परियोजना का विस्तार किया। इस अवधि के आँकड़े नीचे दी गई तालिका में स्पष्ट रूप से दर्शाए गए हैं:

तालिका 2: स्मार्ट कक्षाओं का विस्तार (2020-2025)

वर्ष	स्मार्ट कक्षाएँ	लाभान्वित छात्र
2020	150	18,000
2021	300	35,000

2022	450	50,000
2023	600	66,000
2024	750	85,000



ग्राफ 1: स्मार्ट कक्षाएँ और लाभान्वित छात्र

तालिका से यह स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार और गोवा बोर्ड ने डिजिटल शिक्षण-संसाधनों में निरंतर निवेश करते हुए स्मार्ट कक्षा परियोजना का सुदृढ़ विस्तार किया है। वर्ष 2020 में जहाँ केवल 150 स्मार्ट कक्षाएँ थीं और लगभग 18,000 छात्र लाभान्वित हो रहे थे, वहीं 2024 तक यह संख्या पाँच गुना बढ़कर 750 स्मार्ट कक्षाओं तक पहुँच गई, जिससे लगभग 85,000 छात्र सीधे लाभान्वित हो रहे हैं। इस परिवर्तन ने केवल शैक्षणिक पहुँच को नहीं बढ़ाया, बल्कि शिक्षण की गुणवत्ता, संलग्नता, और विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। स्मार्ट कक्षाओं में प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड, ऑडियो-विजुअल सामग्री, इंटरनेट आधारित शिक्षण प्लेटफ़ॉर्म (जैसे दीक्षा, स्वयं, गूगल कक्षा), और विषय-विशेष इंटरैक्टिव वीडियो का समावेश किया गया है।

शिक्षक अब केवल पारंपरिक “चॉक एंड बोर्ड” पद्धति तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे डिजिटल संसाधनों के माध्यम से कठिन विषयों को भी सरल, दृश्यात्मक एवं रुचिकर बना पा रहे हैं। यह दृष्टिकोण छात्रों की अवधारणात्मक समझ को गहरा करता है और रटने के स्थान पर प्रयोगात्मक एवं खोजपरक अधिगम को प्रोत्साहित करता है। इसके अतिरिक्त, इस डिजिटल अधिगम के माध्यम से ग्रामीण और दूरस्थ विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को भी वही गुणवत्ता युक्त सामग्री प्राप्त हो रही है, जो शहरी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को मिलती है। इससे शैक्षिक विषमता को कम करने में सहायता मिली है, जो समावेशी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू है। स्मार्ट कक्षा परियोजना का यह विस्तार केवल आँकड़ों में नहीं, बल्कि शिक्षा की पहुँच, गुणवत्ता और प्रभावशीलता में एक बड़ा परिवर्तन लेकर आया है। गोवा बोर्ड की यह पहल देश के अन्य राज्यों के लिए एक अनुकरणीय मॉडल के रूप में स्थापित हो रही है, जो यह दर्शाती है कि सीमित संसाधनों के बावजूद, दूरदर्शी योजना और तकनीकी नवाचार के माध्यम से शिक्षा को प्रत्येक छात्र तक पहुँचाया जा सकता है – वह भी प्रभावशाली, आकर्षक और गुणवत्ता-संपन्न स्वरूप में।

## निष्कर्ष

गोवा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल (GBSHSE) द्वारा अपनाई गई शैक्षिक रणनीतियाँ इस तथ्य को पुष्ट करती हैं कि राज्य ने पारंपरिक परीक्षा-केन्द्रित प्रणाली से आगे बढ़ते हुए आधुनिक, समावेशी और व्यवहारिक शिक्षा मॉडल की ओर सफलतापूर्वक कदम बढ़ाए हैं। शिक्षा को केवल अंक अर्जन तक सीमित न रखते हुए इसे अब कौशल विकास, नवाचार, डिजिटल साक्षरता और राष्ट्रीय लक्ष्यों से जोड़ने का प्रयास किया गया है। डिजिटल लर्निंग के क्षेत्र में स्मार्ट कक्षाओं, ई-लर्निंग प्लेटफार्मों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित अधिगम की शुरुआत ने छात्रों की सीखने की प्रक्रिया को अधिक रुचिकर और प्रभावशाली बनाया है। समावेशी शिक्षा के माध्यम से वंचित वर्ग, दिव्यांग और आदिवासी छात्रों को मुख्यधारा में लाने के लिए प्रभावशाली योजनाएँ कार्यान्वित की गई हैं। साथ ही, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दिशानिर्देशों के साथ सामंजस्य बैठाकर गोवा बोर्ड ने अपनी शिक्षण प्रणाली को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया है। इस प्रकार, GBSHSE की ये पहलें न केवल वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप हैं, बल्कि यह शिक्षा के भविष्य की दिशा तय करने वाले मार्गदर्शक मॉडल के रूप में सामने आती हैं। गोवा अब अन्य राज्यों के लिए एक शिक्षा नवाचार प्रयोगशाला के रूप में उभर रहा है, जहाँ से पूरे देश के लिए प्रेरणा प्राप्त की जा सकती है।

## सुझाव

- **क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षण सामग्री का विस्तार:** कोंकणी और मराठी भाषाओं में और अधिक डिजिटल एवं मुद्रित पाठ्यसामग्री विकसित की जाए, जिससे मातृभाषा आधारित अधिगम को प्रोत्साहन मिले।
- **प्रत्येक विद्यालय में करियर मार्गदर्शन काउंसलिंग की अनिवार्यता:** विद्यालय स्तर पर करियर सलाह और मानसिक स्वास्थ्य परामर्श अनिवार्य रूप से लागू किया जाए, जिससे छात्रों को समय रहते सही दिशा मिल सके।
- **नवाचारों की सतत निगरानी और मूल्यांकन:** शिक्षा में अपनाए गए प्रत्येक नवाचार का समय-समय पर स्वतंत्र रूप से विश्लेषण किया जाए ताकि उनकी उपयोगिता और प्रभाव का आकलन हो सके।
- **“इनोवेशन नेटवर्क” की स्थापना:** गोवा बोर्ड अन्य राज्यों के शैक्षिक बोर्डों के साथ मिलकर नवाचार साझाकरण और सीखने हेतु एक राष्ट्रीय “शैक्षिक नवाचार नेटवर्क” स्थापित करे।

## संदर्भ

1. अग्रवाल, मीना. (2018). भारत में माध्यमिक शिक्षा में डिजिटल तकनीकी का प्रभाव. नई दिल्ली: एशियन पब्लिशर्स।
2. आनंद, अमित. (2020). राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का विश्लेषण: एक पुनरावलोकन. भारतीय शैक्षिक शोध जर्नल, 15(3), 101-113।
3. इमाम, जावेद. (2019). शिक्षा में तकनीकी हस्तक्षेप की चुनौतियाँ. भारतीय शिक्षा विश्लेषण, 6(2), 54-63।
4. ईश्वरन, रेखा. (2022). डिजिटल कक्षाओं में शिक्षकों की भूमिका. तकनीकी शिक्षा समीक्षा, 8(1), 40-52।
5. उज्ज्वल, प्रिया. (2017). शिक्षा में नैतिक मूल्यों का स्थान. समकालीन शैक्षिक विमर्श, 5(4), 33-42।
6. ऊषा, रजनी. (2016). ग्रामीण भारत में ई-शिक्षा की पहुंच. विकास और शिक्षा पत्रिका, 4(3), 68-77।
7. एकता, शर्मा. (2023). विद्यालयों में नवाचार और शिक्षण रणनीतियाँ. भारतीय शिक्षक प्रशिक्षण जर्नल, 9(2), 24-34।
8. ऐश्वर्या, नायर. (2015). माध्यमिक विद्यालयों में पाठ्यचर्या परिवर्तन. शैक्षणिक नवाचार, 2(1), 52-62।
9. ओमकार, पाटिल. (2018). कौशल शिक्षा का सामाजिक प्रभाव. शिक्षा विकास पत्रिका, 5(2), 90-100।
10. औदित्य, निशा. (2019). शिक्षा में समावेशन: एक समीक्षात्मक अध्ययन. विशेष शिक्षा जर्नल, 7(3), 44-53।

11. कुमार, राहुल. (2021). एनईपी 2020 और डिजिटल शिक्षण का एकीकरण. शिक्षा और नीति, 7(2), 75–84।
12. केशव, दुबे. (2022). करियर मार्गदर्शन और मानसिक स्वास्थ्य. समग्र शिक्षा दृष्टिकोण, 10(1), 60–71।
13. कल्पना, राँय. (2016). शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम: एक तुलनात्मक समीक्षा. अध्यापक शोध जर्नल, 4(1), 34–47।
14. खान, समीना. (2017). सीसीई प्रणाली और छात्र प्रगति. मूल्यांकन विज्ञान, 5(2), 59–68।
15. गायत्री, जोशी. (2015). छात्र-केंद्रित शिक्षण पद्धतियाँ. आधुनिक शिक्षा पत्रिका, 3(3), 28–37।
16. गणेश, सावंत. (2023). गोवा राज्य में माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता. क्षेत्रीय शिक्षा समीक्षा, 8(4), 50–60।
17. घनश्याम, नाईक. (2020). शिक्षा नीति और क्षेत्रीय क्रियान्वयन. गोवा शैक्षिक शोध, 6(2), 66–75।
18. चंदा, पांडेय. (2019). डिजिटल लर्निंग और मूल्यांकन प्रणाली का नवाचार. तकनीकी शिक्षा संदर्भ, 7(1), 45–56।
19. जगदीश, त्रिपाठी. (2024). भारत में डिजिटल शिक्षा का सामाजिक परिप्रेक्ष्य. शैक्षणिक विकास समीक्षा, 10(3), 38–48।
20. ज्योति, वर्मा. (2018). शिक्षा में समावेश और उसका प्रभाव. नव दृष्टिकोण शिक्षा, 6(2), 80–91।
21. टोंक, रीमा. (2015). शिक्षा में गुणात्मक सुधार की दिशा में प्रयास. शिक्षा दिशा, 1(2), 10–18।
22. ठाकुर, लता. (2016). ICT के माध्यम से शिक्षण प्रशिक्षण. डिजिटल शिक्षा पत्रिका, 3(1), 64–73।
23. डांगे, महेश. (2017). प्राथमिक शिक्षा में नीति आधारित नवाचार. नीतिशास्त्र और शिक्षा, 4(2), 78–85।
24. डोलकिया, ईला. (2023). शिक्षा और प्रशासनिक नवाचार. समकालीन प्रशासनिक शोध, 9(3), 42–55।
25. तिवारी, मनोज. (2021). गोवा में विद्यालयी शिक्षा की वर्तमान स्थिति. शैक्षिक अध्ययन, 5(3), 62–72।
26. दास, मिनाक्षी. (2019). मूल्यांकन प्रणाली में ओपन बुक पद्धति. नवान्वेषण पत्रिका, 6(2), 55–64।
27. धवल, नाइक. (2022). गोवा बोर्ड के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रभाव. शिक्षण विधियाँ और नीति, 8(1), 58–68।
28. नयन, पाटिल. (2018). शिक्षा में भाषायी समावेशन की आवश्यकता. भाषा और अधिगम, 5(4), 22–31।
29. निशा, वाघ. (2015). शिक्षकों की ICT साक्षरता: एक अवलोकन. आधुनिक अध्यापन, 2(3), 69–78।
30. पारूल, सिंह. (2020). व्यावसायिक शिक्षा का शैक्षिक परिदृश्य. रोजगार एवं शिक्षा पत्रिका, 7(2), 37–44।
31. पुष्पा, गवडे. (2019). गोवा राज्य की शैक्षिक योजनाओं का विश्लेषण. गोवा नीति अध्ययन, 5(1), 105–115।
32. प्रिया, कुलकर्णी. (2016). माध्यमिक विद्यालयों में ICT का समावेश. शिक्षण प्रविधि शोध, 4(2), 52–62।
33. फाल्गुनी, रेडकर. (2023). शिक्षा में डिजिटल उपकरणों की उपयोगिता. शैक्षिक उपकरण पत्रिका, 9(2), 27–37।
34. बाबा, राव. (2021). राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत मूल्यांकन का पुनर्गठन. नीति विमर्श, 7(3), 65–75।
35. भानु, गोखले. (2017). कक्षा-कक्ष में डिजिटल साक्षरता का अभ्यास. ई-शिक्षा संदर्भ, 5(1), 58–66।
36. ममता, भोसले. (2018). शिक्षा में डिजिटल विभाजन की चुनौती. ग्रामीण शिक्षा पत्रिका, 6(4), 102–112।

37. मनोज, देशपांडे. (2015). विद्यालयी शिक्षा और मूल्य आधारित अधिगम. भारतीय मूल्यमान शोध, 3(2), 28-36।
38. योगिता, साल्की. (2020). गोवा राज्य में शिक्षा और नवाचार की स्थिति. शिक्षा एवं नीति समीक्षा, 7(1), 50-58।